अत्यन्त महत्वपूर्ण
विधानसभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली–92

फा0 सं सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./2018/ 197 दिनांकः 21/03/2018

सेवा में,

उप सचिव(प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली –54.

विषयः दिल्ली विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 352 दिनांक 27.03.2018 को सदन की बैठक हेतु ।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्वत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीया,

लक्ष्मी कृष्णन

(लक्ष्मी कृष्णन)
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियों सहित ।

लक्ष्मी कृष्णन

उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

22/3/18

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम - उद्योग विभाग

विभाग का पता - ४१९, उद्योग सदन, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली - 110092

अतारांकित प्रश्न संख्या - ३५२

दिनांक - २७.०३.२०१८

प्रश्नकर्ता का नाम . श्री रामचन्द्र, विधायक

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि बवाना फैक्ट्री एरिया में डीएसआईआईडीसी में 16000 फैक्ट्री हैं और ये इस क्षेत्र का सबसे बडा इंडस्ट्रियल एरिया है।	जी हॉ ।
ख)	क्या यह भी सत्य है कि यहां कार्यरत उद्यमियों को सर्विस टैक्स जमा करने 40-45 कि.मी. दूर पटपडगंज बैंक जाना पडता है।	जी नही, डीएसआईआईडीसी में पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत कोई सर्विस टैक्स नही लिया जाता ।
ग)	क्या सरकार इन फैक्ट्री मालिकों को अपना अपना टैक्स बवाना या आसपास जमा कराने की सुविधा देने पर विचार कर रही है।	पट्टा किराया (Lease Rent) तथा अन्य देय राशी का online भुगतान डीएसआईआईडीसी की वेबसाईट www.dsiidc.org पर उपलब्ध "Allottees Friendly Portal" के माध्यम से किया जाता है।
घ)	यदि हॉ, तो कब तक यह सुविधा शुरू कर दी जायेगी।	
च)	क्या यह भी सत्य है कि बवाना में डीएसआईआईडीसी के खाली पडे ऑफिस भवन में डीएसआईआईडीसी का ऑफिस शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है, और	जी नही, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।
छ)	यदि हॉ, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ?	

अरुण मिश्रा

(अरुण मिश्रा)

विशेष आयुक्त (उद्योग)

Scanned by CamScanner